विशेषांकः कॉन्क्लेव 2026

इंडिया टुडे

1 अप्रैल, 2026 60 रुपए

उपलब्धियां और अवरोध

(बाएं से क्रमशः) ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि अब्दुल माजिद हकीम इलाही; मशहूर लेखिका मेय मस्क; ओपनएक्सओ के संस्थापक सलीम इस्माइल; डोनाल्ड ट्रंप के खेमे की लॉरा लूमर; अभिनेता अक्षय कुमार; सिग्नल की अध्यक्ष मेरेडिथ व्हिटेकर; क्रिकेटर संजू सैमसन; अदाणी पोर्ट्स के एमडी करण अदाणी; भारत में अमेरिकी राजदूत सार्जियो गोर; इज़्राएल के राजदूत रुवेन अज़ार; और वेदांता के अनिल अग्रवाल

RNI NO. 45823/1986 REGISTRATION NO. DL(DS)-02/MP/2025-26-27, DL(ND)-11/6042/2024-25-26; LICENSED TO POST WPP NO U(C)-31/2024-26; FARIDABAD/46/2026-28 www.indiatodayhindi.com

OC
अग्रिम सप्ताह के लिए प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित; एलपीसी दिल्ली-आरएमएस-दिल्ली-110006 से प्रत्येक शनिवार और सोमवार को प्रेषित; कुल पन्नों की संख्या 68 (आवरण सहित) वर्ष 40; अंक: 17

ऊर्जा सुरक्षा तेजी से बढ़ते भारत के लिए

अपने संसाधनों की खोज-खबर

अनिल अग्रवाल, *चेयरमैन, वेदांता समूह*

अब जब भू-राजनीतिक तनाव भारत की ऊर्जा संबंधी कमजोरियों को उजागर कर रहे हैं, ऐसे में वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने एक सीधा संदेश दिया है: आयातित संसाधनों पर भारत की निर्भरता एक नीतिगत विफलता है, न कि कोई भौगोलिक बाध्यता. इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में उन्होंने संसाधनों की कमी की आम चर्चा को नजरअंदाज करते हुए दलील दी कि भारत में दरअसल प्राकृतिक संसाधन भरपूर हैं. उन्होंने कहा कि समस्या यह है कि देश संसाधनों को कुशलतापूर्वक नहीं निकाल पा रहा और दक्षता से उनका उपयोग करने में असमर्थ है. भारत का 60 फीसद से ज्यादा आयात खनिज और ऊर्जा से जुड़े होने के कारण उन्होंने इस मसले को नियमित सुधार के बजाए रणनीतिक तौर पर अनिवार्य बताया.

अग्रवाल ने बार-बार उन बातों की ओर इशारा किया जिन्हें वे गहरी जड़ें जमा चुकी ढांचागत कमियों, मंजूरी में देरी, जरूरत से ज्यादा नियम-कायदों और निजी उद्यमों पर संस्थागत भरोसे की कमी मानते हैं. उनका तर्क है कि इसके फलस्वरूप क्षमता का बहुत कम इस्तेमाल हो पाता है, खासतौर पर सरकारी कंपनियों में. सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों को खरीदने और उनका विस्तार करने के वेदांता के अनुभव का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि इनमें से कई उद्यम अपनी पूरी क्षमता से बहुत कम पर काम करते हैं; अक्सर इसकी वजह तकनीकी बाधाओं के बजाए नौकरशाही की सुस्ती होती है.

दक्षता के अलावा अग्रवाल जोरदार आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रति भी मुखरता से बोले. उनका कहना था कि वैश्विक ताकतों की इसमें थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं है कि भारत ऊर्जा और खनिज के मामले में आत्मनिर्भर बने; इसके बजाए वे यही चाहती हैं कि भारत आयात पर निर्भर बड़ा बाजार ही बना रहे. चाहे इसे एक रणनीतिक अंतर्दृष्टि के तौर पर देखा जाए या फिर महज बयान के तौर पर, यह बात घरेलू क्षमता-निर्माण के लिए उनके व्यापक तर्क को ही आगे बढ़ाती है.

अग्रवाल का मुख्य सुझाव यह है कि सरकार कारोबार के साथ जिस तरह से पेश आती है, उसमें बुनियादी बदलाव किए जाएं. उन्होंने जोर दिया कि 'ज्यादा नियंत्रण वाले रेगुलेटरी सिस्टम' की जगह भरोसे पर आधारित ऐसा ढांचा तैयार किया जाए, जो सेल्फ-सर्टिफिकेशन और कम से कम दखल पर आधारित हो.

वेदांता के संस्थापक ने एक और बारीक बदलाव की ओर इशारा किया—भारतीय उद्यमियों में जोखिम उठाने की घटती भावना. उन्होंने तर्क दिया कि जहां पहले की पीढ़ियां बढ़ोतरी पर जोरदार तरीके से दांव लगाने को तैयार रहती थीं, वहीं आज के निवेशक ज्यादा सतर्क हैं—जिसकी एक वजह सिस्टम से जुड़ी रुकावटें हैं. उन्होंने सुझाव दिया कि अगर भारत तेल, गैस और खनन जैसे सेक्टरों में बड़े पैमाने पर निवेश चाहता है तो इस रुझान को पलटना बहुत जरूरी होगा.

अग्रवाल ने खासतौर पर पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं को कम करके आंका जो अक्सर संसाधनों से जुड़ी परियोजनाओं को रोक देती हैं. उनका तर्क था कि तकनीक काफी हद तक जोखिम कम कर सकती है और खनन को जरूरी आर्थिक गतिविधि के तौर पर देखा जाना चाहिए, न कि बोझ के रूप में. यह रुख, भले ही विवादित हो, बड़े पैमाने पर घरेलू उत्पादन तेज करने के उनके जोर के अनुरूप है.

सत्र का संदेश स्पष्ट था: भारत में संसाधनों, पूंजी या क्षमता की कमी नहीं है. अग्रवाल के अनुसार, देश में कमी एक ऐसे सिस्टम की है जो अपने कारोबारों पर यह भरोसा करता हो कि वे काम करेंगे.■

खास बातें

- आयात पर भारत की निर्भरता ढांचागत है न कि स्वाभाविक. संसाधनों की कमी एक मिथ है; असली मुद्दा है नीतिगत अक्षमता और घरेलू भंडारों का कम उपयोग.
- नियामकीय व्यवस्था सबसे बड़ी अड़चन है. देरी, अनुपालन बोझ और भरोसे की कमी निवेश को हतोत्साहित कर रही है और संसाधनों के विकास को धीमा कर रही है.
- निजी क्षेत्र खासा मूल्य सृजित कर सकता है. विनिवेश का अनुभव बताता है कि इससे रिसोर्स इंडस्ट्रीज में उत्पादन और दक्षता आश्चर्यजनक ढंग से बढ़ाई जा सकती है.
- ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता अब एक रणनीतिक आवश्यकता है. निर्भरता घटाना आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है.

> **या तो आप हमेशा गरीब बने रहें और पश्चिम एशिया पर आश्रित रहें, अगले 100 साल तक भी उनका तेल-गैस खरीदते रहें या फिर आप अपना उत्पादन शुरू कर दें.**

बंदीप सिंह

भारत में अकूत क्षमता है. धरती की सतह पर तो यह कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया है लेकिन हमने धरती के नीचे मौजूद संसाधनों को अभी तक भी विकसित नहीं किया है.

भारत की भू-गर्भीय संरचना दुनिया में सबसे बेहतरीन संरचनाओं में से एक है. विदेशी मुल्क कतई नहीं चाहते कि भारत अपने संसाधनों को निकाले. वे चाहते हैं कि यह देश केवल एक बाजार ही बना रहे.